**प्रसार भारती**
**भारतीय प्रसारण निगम**
**आकाशवाणी केन्द्र शिमला**
**20.12.2024 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे**

## "आज के मुख्य समाचार"

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा– स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत।
- प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तिथि से नहीं मिलेंगे वरिष्ठता व वित्तीय लाभ।
- प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार शून्यकाल की व्यवस्था शुरू– सदस्यों ने उठाए अपने–अपने क्षेत्रों के मुद्दे।
- भाजपा ने नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मियों व गैस्ट टीचर पॉलिसी के विरोध में धर्मशाला में किया प्रदर्शन।
- सांसद सिकंदर कुमार ने केंद्र के सहयोग से हिमाचल में चल रहे विभिन्न कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार।

**समाचार विस्तार से.....**

**प्रश्नकाल**

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माना है कि प्रदेश में इस समय स्वास्थ्य सेवाएं बहुत निचले स्तर पर हैं। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान सदन में विधायक दीपराज के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी माना कि राज्य में लगभग हर स्वास्थ्य संस्थान में स्टाफ की कमी है और सरकार इसे दूर करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रेडियोग्राफरों की सबसे अधिक कमी है और इनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार रेडियोग्राफर को दिए जाने वाले वेतन में भी वृद्धि करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आईजीएमसी शिमला में एक सौ 33 टेस्ट निशुल्क कर रही है, जबकि कमला नेहरू अस्पताल में 42 टेस्ट निशुल्क हैं। विधायक अजय सोलंकी के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में बंदरों की समस्या को कम करने के लिए बरसात के दौरान किए जाने वाले पौधरोपण में 60 फीसदी पौधे फलदार लगाएगी। विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास जारी हैं और निगम की आय में बढ़ोतरी हो रही है।

## प्रश्नकाल–2

उन्होंने प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली एचआरटीसी के सुचारू संचालन के लिए सभी लोगों, खासकर विपक्षी दल भाजपा का सहयोग मांगा है। अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी के 96 फीसदी रूट घाटे के हैं। इसके बावजूद निगम में न तो किसी कर्मचारी का वेतन बकाया है और न ही पेंशन की राशि बकाया है। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधायक विनोद कुमार के मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2023–24 और 2024–25 के दौरान अभी तक 81 हज़ार 9 सौ 28 आवासों की पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

## विधेयक

अदालती आदेशों के बाद वरिष्ठता सूची में संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे प्रदेश के हजारों अनुबंध कर्मचारियों को अब ज्वाइनिंग की तिथि से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। राज्य में कर्मचारियों के भर्ती व पदोन्नति नियमों में बदलाव संबंधी विधेयक आज सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा की शर्तें विधेयक 2024 को पेश किया था। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आज मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के कुछ अनुबंध कर्मचारी अदालत गए थे और उन्होंने ज्वाइनिंग की तिथि से नियमितीकरण का लाभ मांगा था। अदालत ने भी इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था और इस तरह के फैसलों से अनुबंध का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि अनुबंध वाले कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तिथि से वरिष्ठता दी जाती है तो सरकार को बड़ी संख्या में पहले से ही नियमित कर्मचारियों को डिमोट करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक प्रदेश हित में है और इससे सरकार पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ भी कम होगा। उन्होंने इस विधेयक को लेकर विपक्ष द्वारा जताई गई शंकाओं को खारिज कर दिया।

## संकल्प पारित

प्रदेश विधानसभा ने वन संरक्षण अधिनियम–1980 में संशोधन कर आपदाओं में खेती योग्य भूमि बह जाने पर तबादले में सरकारी वन भूमि व लघु और सीमांत किसानों को 10 बीघा तक सरकारी वन भूमि खेती करने के लिए देने संबंधी सरकारी संकल्प को आज सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस संकल्प में केंद्र सरकार से एफसीए कानून में संशोधन की मांग की गई है ताकि सरकार प्रभावितों को वन भूमि खेती के के लिए आवंटित कर सके। यह संकल्प राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में चर्चा के लिए पेश किया था। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल में हर साल आपदाओं से खासकर जमीन को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन एफसीए कानून के कारण सरकार तबादले में प्रभावितों को जमीन नहीं दे पा रही है। यह स्थिति तब है जबकि वन भूमि की मालिक प्रदेश सरकार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस संकल्प के माध्यम से केंद्र सरकार से अधिकतम 10 बीघा जमीन आवंटित करने के लिए कानून में संशोधन की मांग की है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र से इस

कानून में आपदाओं के अलावा अन्य कारणों से प्रभावित लोगों को भी जमीन देने के लिए एफसीए कानून में प्रावधान करने का आग्रह किया गया है।

**शून्यकाल**

प्रदेश विधानसभा के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। लोकसभा की तर्ज पर अब प्रदेश विधानसभा में भी शून्यकाल की व्यवस्था कर दी गई है। **विस्तृत ब्यौके के साथ ये रिपोर्ट.....**

*वीओ– हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज से शून्यकाल की व्यवस्था शुरू हो गई है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार सदन में शून्यकाल के तहत सदस्यों ने मुद्दे उठाए। शून्यकाल की शुरूआत के साथ ही न केवल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, बल्कि इस व्यवस्था के तहत पहला मुद्दा उठाने वाली कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि विधानसभा में नई परंपरा जुड़ गई है। उन्होंने शून्यकाल की व्यवस्था शुरू करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को बधाई दी। सत्र के तीसरे दिन शून्यकाल के दौरान लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने टोल टैक्स का पहला मामला उठाया। इसका जवाब देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एनएचएआई के समक्ष यह मामला उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी तब भी टोल टैक्स को स्थगित किया गया था। विक्रमादित्य सिंह ने विधायक को आश्वासन दिया कि केंद्र के समक्ष इस मामले को उठाया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सकें। विधायक हरदीप सिंह बावा ने नालागढ़ में स्थापित होने वाले एथनॉल प्लांट में उपयोग होने वाले भू जल का मामला शून्य काल में उठाया। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भू–जल दोहन के मामले में उनके विभाग की टीम उद्योगों का निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि भू–जल दोहन के मामले में एमओयू की अवहेलना करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई की जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में भू जल स्तर नीचे जा रहा है। 70 फीसदी भू–जल का दोहन किया जा चुका है। भावी पीढियों के लिए हमें इस बारे सोचने की आवश्यकता है। विधायक त्रिलोक जमवाल द्वारा उठाए गए मामले पर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नई पंचायतों के गठन के लिए प्रस्ताव डीसी या विधायक सीधे भी भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि ग्राम सभा के माध्यम से यह प्रस्ताव भेजे जाने हैं, लेकिन कई पंचायतें इसमें रुचि नहीं ले रही है। विधायक डॉक्टर जनकराज केवल सिंह पठानिया, सुखराम चौधरी और संजय रतन ने ने भी शून्यकाल के दौरान अपने–अपने विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित मामले उठाए।*

*धर्मशाला से हमारे विशेष संवाददाता रितेश कपूर के साथ समाचार कक्ष से मैं प्रभा शर्मा।*

**प्रदर्शन**

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विपक्षी दल भाजपा ने आज धर्मशाला में विधानसभा परिसर के बाहर नौकरी से निकले गए आउटसोर्स कर्मियों और गेस्ट टीचर पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष प्रदेश सरकार की गेस्ट टीचर भर्ती पॉलिसी का विरोध करता है, क्योंकि यह पॉलिसी प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश के युवाओं के हितों की लड़ाई सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ेगी।

**सिकंदर कुमार**

राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री सिकंदर कुमार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रदेश में रेलवे विस्तार सहित मंडी, पांवटा साहिब, हमीरपुर व बिलासपुर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के निर्माण का विषय रखा। सिकंदर कुमार ने प्रधानमंत्री से बिलासपुर स्थित एम्स में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने और किन्नौर व रेणुका बांध के लिए केंद्र से शीघ्र धनराशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सभी विषयों पर गंभीरतापूर्वक आगामी कार्यवाही का आश्वासन दिया। सिकंदर कुमार ने हिमाचल में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहे विभिन्न कार्यों के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।

## मुख्य समाचार एक बार फिर'

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा– स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत।
- प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तिथि से नहीं मिलेंगे वरिष्ठता व वित्तीय लाभ।
- प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार शून्यकाल की व्यवस्था शुरू– सदस्यों ने उठाए अपने–अपने क्षेत्रों के मुद्दे।
- भाजपा ने नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मियों व गैस्ट टीचर पॉलिसी के विरोध में धर्मशाला में किया प्रदर्शन।
- सांसद सिकंदर कुमार ने केंद्र के सहयोग से हिमाचल में चल रहे विभिन्न कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार।

---